nt>

Title: Need to extend the tenure of "Vidarbha Vaidhanik Board" for five years.

MR. SPEAKER: Let there be at least one day for hon. Members to raise issues.आप लोग बैठिये। यह ठीक नहीं है। क्या बात है, आप क्यों खड़े हैं? जिनके नाम लिस्ट में हैं, मैं उन्हें बुलाऊंगा।

...(*Interruptions*)

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत के स्वर्गीय राट्रपति डा. शंकर दयाल शर्मा को जो आज हमारे बीच नहीं हैं। उन्होंने महाराष ट्र में संविधान की धारा 371 (2) के अंतर्गत विदर्भ ऐरिया के लिये 1994 में डेवलेपमेंट बोर्ड का गठन किया था जिसकी अवधि 5 वर्ा की थी। आप जानते हैं कि पौलिटिकल पार्टीज द्वारा एजैंडा डेवलेपमेंट होता है लेकिन इलैक्शन होने के बाद एजैंडा बदल जाता है। इस प्रकार विदर्भ के साथ इनजस्टिस किया गया है। In 1995, the BJP-Shiv Sena Government came to power and recommended the extension of the same Board for five years. लेकिन मझे यह मुद्दा यहां इसलिये उठाना पड़ रहा है क्योंकि जब 1999 में बीजेपी-शिवसेना की सरकार चली गई, उसके बाद वहां कांग्रेस की सरकार आई। विदर्भ के लिये 5200 करोड़ रुपये का बैकलॉग था। महाराट्र की स्टेट गवर्नमेंट को संविधान की धारा 371(2) के अधीन इस विदर्भ डेवलेपमेंट बोर्ड को पांच साल के लिये बढ़ाना चाहिये था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराट्र की उस कैबिनेट ने एक साल का एक्सटैंशन दिया। वह एक्सटैंशन दि. 30.04.2005 को खत्म होने जा रहा है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि आज जो महाराट्र की स्थिति है, जो एक डेवलप्ड स्टेट था, हिंदुस्तान में जिसका नाम था।

MR. SPEAKER: Is it the duty of the Central Government or the State Government?

...(*Interruptions*)

श्री सुबोध मोहिते : महाराट्र जो एक डेवलप्ड स्टेट थी, आज वहां पानी की व्यवस्था तक नहीं है। श्री शिवराज पाटील और श्री गुलाम नबी आजाद यहां पर है। जिन्होंने महाराट्र के विदर्भ से चुनाव लड़ा है। आज महाराट्र में बिजली की व्यवस्था बदतर है तथा महाराट्र सरकार ने वहां अकाल पास किया है और 200 करोड़ रुपये की डिमांड यहां से की है। आज वहां आत्महत्या की स्थिति है। जैसा नीतीश कुमार जी ने अभी बिहार का मामला यहां उठाया, सेम सिचुएशन महाराट्र में है। मैं कहना चाहता हूं कि इस डेवलपमैन्ट में पोलिटिक्स होने की बहुत संभावना है। जो एक्सपायरी डेट 30.04.2005 को खत्म होने जा रही है। सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट की होम मिनिस्ट्री से राज्यपाल को डायरेक्टिव जाता है, तब बोर्ड का नोटिफिकेशन निकलता है। मेरी प्रार्थना है कि गृह मंत्री जी यहां मौजूद है। अगर महाराट्र की कैबिनेट यह डेवलपमैन्ट बोर्ड पांच साल के लिए रिकमैंड नहीं करता है तो इसे ध्यान में रखते हुए, विदर्भ के बैकलॉग को कंसीडर करते हुए, इसे कम्पैल करने के लिए यहां से डायरेक्टिव जानी चाहिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

MR. SPEAKER: Shri Brajesh Pathak, I will tell you that in future you will not get a chance. You remember this warning.

...(*Interruptions*)

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव) : सर, हमने तो कोई गलती नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिये, बहुत हो गया।